

प्रेषक,

एम०एच० खान,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

१. प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।
२. मुख्य महाप्रबन्धक,  
उत्तराखण्ड जल संस्थान,  
देहरादून।

३. निदेशक,  
स्वजल परियोजना,  
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-२

देहरादून : दिनांक १२ जून, २००९

विषय :- वित्तीय वर्ष २००९-१० में सैक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम का पत्र संख्या ०१/कैम्प देहरादून दिनांक २२.०५.२००९, मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान का पत्र संख्या ५७१/स्वैप (धनावंटन)/२००८-०९ दिनांक १९.०५.२००९ एवं निदेशक, स्वजल का पत्र संख्या २९२ E-३८(VIII)/२००९ दिनांक १८.०५.२००९ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि घालू वित्तीय वर्ष २००९-१० में सैक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए क्रमशः उत्तराखण्ड पेयजल निगम हेतु ₹० १५.०० करोड़, उत्तराखण्ड जल संस्थान हेतु ₹० १५.०० करोड़ एवं स्वजल, परियोजना हेतु ₹० २५.०० करोड़ अर्थात् कुल ₹० ५५.०० करोड़ (₹० पच्चपन करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्देशन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२. उपरोक्त तीनों संस्थाओं हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण क्रमशः प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं निदेशक, पी०एम०य०, स्वजल परियोजना, देहरादून के हस्ताक्षर से तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर पश्चात् बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार किस्तों में ही आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउधर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद सुपलब्ध करायी जायेगी।

३. यह स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन दी जा रही है कि धनराशि के बिल स्वीकृत/अनुमोदित मर्दों पर ही व्यय की जायेगी। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति होनी है। अतः विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित अनुबन्ध Project Appraisal Document (PAD) आपरेशन मैनुअल तथा Procurement Manual आदि व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

5. साथ ही व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेंशियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अधिवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। कार्य में उत्तराखण्ड अधिग्राहित नियमावली, 2008 के साथ नियमों का अनुपालन किया जायेगा। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आंगणनों/पुनरीक्षित आंगणनों को निर्भित कराकर उन पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आंगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। इसके साथ ही समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्त मितव्यता सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार ही व्यय किया जाय और मितव्यता वरती जाय।

6. उपरोक्त प्रस्तार-3 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग एवं उपक्रम में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार से विचलन पाया जाता है तो सर्वधित वित्त नियंत्रक आदि का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा तथा वे सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7. प्रश्नगत स्वीकृत विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति की प्रत्याशा में दी जा रही है। अतः स्वीकृत की जा रही तथा पूर्ण स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च 2009 तक उपयोग कर उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रतिपूर्ति दावा तत्काल विश्व बैंक को प्रेषित करते हुए स्वीकृत धनराशि की प्रतिपूर्ति यथाशीघ्र सुनिश्चित की जायेगी और प्रतिपूर्ति होने पर उसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी। पूर्व स्वीकृत व अब स्वीकृत की जा रही धनराशि के विपरीत किसी धनराशि की प्रतिपूर्ति होने पर ही आगामी किस्त अवमुक्त पूर्व स्वीकृत धनराशि से पूर्ण उपयोग के बाद ही की जायेगी। विगत में स्वीकृत धनराशि की ₹0 12.00 करोड़ के लगभग छे दावों के आडिट के अभाव में प्रतिपूर्ति दावे भारत सरकार को प्रेषित नहीं किये गये हैं। अतः 1-2 माह के अन्दर शीघ्र आडिट कराकर उसके प्रतिपूर्ति के दावे भारत सरकार को अविलम्ब प्रेषित किये जायें। बिना राज्य सरकार के द्वारा अवमुक्त बजट के विपरित 60-70 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति हुए आगामी किस्त अवमुक्त करना सम्भव नहीं होगा। जो अधिकारी उक्त व्यय होने वाले दावों के आडिट करवाने के लिए उत्तरदायी हैं, उसका उत्तरदायित्व का निर्धारण कर उसके पिलहु कार्यवाही की जायेगी।

8. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से तीनों विभागों द्वारा व्यय की गयी धनराशि के व्यय की प्रगति का अनुश्रवण राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पेयजल विभाग, देहरादून द्वारा किया जायेगा तथा समय-समय पर इसकी प्रतिपूर्ति का दावा/मांग विश्व बैंक जो राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पेयजल विभाग, देहरादून द्वारा ही भेजा जाएगा।

9. अवमुक्त धनराशि को उपयोग में लाने से पूर्व योजनाओं ली जूदी पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2215 जलपूर्ति तथा टफाई-01-जलपूर्ति-आयोजनागत-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-97-वाहय/विश्व बैंक सहायतित ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना (वाहय सहायतित)-02-वाहय/विश्वबैंक सहायतित ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना (द्वितीय चरण)-20-सहायक अनुदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 95/XXVII(2)/09 दिनांक 05 जून, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एमोएच० खान)  
सचिव

पृ०स० ५१००/उन्तीस(2)/09-2(३७प०)/२००८ तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमार्यू मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. आयुक्त, ग्राम विकास उत्तराखण्ड देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पेयजल विभाग, देहरादून।
7. समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त (बजट सेल) / नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा० पेयजल मंत्री जी।
10. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
11. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
13. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पैंवार)  
संयुक्त सचिव